इकाई 1 राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता

इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन: प्रकृति और क्षेत्र

1.2.1 तुलना : संबंधों की पहचान

1.2.2 तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार

1.3 तुलनात्मक राजनीति : एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

1.3.1 राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की शुरुआत

1.3.2 19वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध और 20वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध

1.3.3 द्वितीय विश्वयुद्ध और उसके बाद

1.3.4 1970 का दशक और विकासवाद की चुनौतियां

1.3.5 1980 का दशक : राज्य की वापसी

1.3.6 20वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध: भूमंडलीकरण और उभरती प्रवृत्तियां

1.4 राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता

1.4.1 सैद्धांतिक निरूपण के लिए तुलना

1.4.2 वैज्ञानिक अध्ययन के लिए तुलना

1.4.3 संबंधों की व्याख्या के लिए तुलना

1.5 सारांश

1.6 शब्दावली

1.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें और लेख

1.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्रा और उपयोगिता पर विचार-विमर्श करेंगे। इससे आप कुछ प्रश्नों पर विचार कर सकेंगे जैसे :

- तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है अर्थात तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण की खासियत क्या है: इसकी विशिष्टताएं, तत्व, संघटक, दृष्टिकोण, उद्देश्य और उस सैद्धान्तिक संरचनात्मक संदर्भयुक्त ढांचे की जानकारी जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है।
- इसका क्षेत्र क्या है इसके अन्तर्गत इसके कार्य क्षेत्र और विस्तार की चर्चा की जाएगी।
- इसकी उपयोगिता के अन्तर्गत इस बात पर विचार कि राजनैतिक वास्तविकता के समझने में इसका क्या योगदान है। यह बताने की कोशिश की जाएगी कि किस प्रकार तुलनात्मक अध ययन इस वास्तविकता को बेहतर ढंग से समझने में मददगार साबित होता है।

यहां यह बता देना आवश्यक है कि इन पक्षों पर अलग-अलग खानों में विचार नहीं किया जा सकता। राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता को सही ढंग से समझने के लिए इसके ऐतिहासिक विकास को समझना होगा और यह देखना होगा कि किस प्रकार बदलते संदर्भों और सरोकारों में इसका स्वरूप बदलता गया है।

इस इकाई को विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक भाग के अन्त में प्रश्न पूछे गए हैं। इकाई के अन्त में अतिरिक्त अध्ययन के लिए एक सूची दी गई है । कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं जिससे आपको अपनी समझ बढ़ाने में मदद मिलेगी। शब्दावली के अन्तर्गत तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण से सम्बद्ध परिभाषित शब्दावली के अर्थ दिए गए हैं।

1.1 प्रस्तावना

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है तुलनात्मक राजनीति में राजनैतिक परिघटना की तुलना की जाती है। इसमें जांच पड़ताल अर्थात तुलनात्मक अध्ययन की विधि के साथ-साथ जांच पड़ताल के विषय अर्थात राजनैतिक परिघटना पर विचार किया गया है। इकाई 2 तुलनात्मक विधि और तुलना की विधियों में बताया जाएगा कि यह तुलनात्मक अध्ययन केवल तुलनात्मक राजनीति में हीं नहीं किया जाता बल्कि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विषयों में भी इस प्रविधि का उपयोग किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति की विशिष्टिता इसके विषय, शब्दावली और दृष्टिकोण में निहित है। इसी कारण इसकी प्रविधि और अध्ययन-क्षेत्र में विशिष्टता आती है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र में लगातार विकास और बदलाव होता रहा है। इसकी विषयवस्तु, शब्दावली और राजनैतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होता रहा है। यह समझने के लिए कि यह परिवर्तन कहां, कैसे और क्यों हुआ है हमें यह जानना होगा कि एक खास समय में अध्ययन का केंद्र बिन्दु क्या था। उस समय अध्ययन के लिए किन उपकरणों, शब्दावलियों और अवधारणाओं का इस्तेमाल किया गया और जांच पड़ताल का उद्देश्य, दृष्टिकोण और प्रस्थान बिंदु क्या था ? इस प्रकार आने वाले भागों में हम तुलनात्मक राजनीति के विकास की निरंतरता और अनिरंतरता पर विचार करेंगे। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह विकास क्यों और कैसे हुआ ? इसके अलावा उन ऐतिहासिक संदर्भों और सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक शक्तियों की भी चर्चा की जाएगी जिनमें इनका विकास हुआ। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुए भूमंडलीकरण और इस समय हुए मूलभूत परिवर्तनों के कारण तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में भी तेजी से परिवर्तन हुआ।

1.2 राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन : प्रकृति और क्षेत्र

पिछले भाग में हमने बताया है कि अन्य विषयों में भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। हम यह भी जान चुके हैं कि तुलनात्मक अध्ययन उन अन्य विषयों से अलग है जो तुलनात्मक विधि भी अपनाते हैं। यह अलगाव विषय, भाषा और दृष्टिकोण के कारण पैदा होता है। अत: यहां यह प्रश्न पूछना स्वाभाविक है कि क्या तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण एक अलग विषय है या राजनीति विज्ञान का ही एक अंग है। हमें याद रखना चाहिए कि विषय, भाषा, शब्दावली और दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान के तहत तुलनात्मक अध्ययन की विशिष्टता स्थापित करना मुश्किल है क्योंकि तुलनात्मक राजनीति में भी राजनीति विज्ञान के विषय और सरोकारों पर विचार किया जाता है जैसे प्रजातंत्र, संविधान, राजनैतिक दल, सामाजिक आंदोलन आदि। राजनीति विज्ञान विषय के अन्तर्गत तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण की खासियत इस बात में निहित है कि इसके अन्तर्गत प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सोच समझकर तुलनात्मक विधि का उपयोग किया जाता है ताकि राजनीति वैज्ञानिकों को मदद मिल सके।

1.2.1 तुलना: संबंधों की पहचान

कुछ विद्वान तुलनात्मक राजनीति के संबंध में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए और तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण की प्रकृति और क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए इस तुलनात्मक विधि पर बल देते हैं। यह आम धारणा है कि विदेशों अर्थात अपने देश से अलग किसी देश का अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनैतिक अध्ययन है। इस प्रकार की समझ के अनुसार यदि आप अपने देश के अलावा किसी दूसरे देश का अध्ययन कर रहे हैं (उदाहरणस्वरूप यदि कोई अमेरिकी ब्राजील की राजनीति या कोई भारतीय श्रीलंका की राजनीति का अध्ययन कर रहा है) तो आप तुलनावादी कहे जाएंगे। एक गलत धारणा यह भी है कि जिस देश का आप अध्ययन कर रहे हों उसके बारे में सूचना इकट्ठी करना ही प्रमुख कार्य है। इसमें थोड़ी बहुत और अप्रत्यक्ष तुलना से काम चल जाता है। अधिकांश तुलनावादियों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति की विशिष्टता दो या दो से अधिक देशों के अध्ययन और उनकी सप्रयत्न तथा सुनियोजित तुलना में निहित होती है जिसमें दो या दो से अधिक देशों की विशेषताओं की पहचान की जाती है और विश्लेषण की जाने वाली विशेष परिघटना के संदर्भ में उनके बीच की समानता और अंतर को स्पष्ट किया जाता है। काफी लम्बे समय से तुलनात्मक राजनीति समानताओं और असमानताओं , वर्गीकरण, राजनैतिक परिघटना के ध्रुवीकरण या द्विभाजन तक सीमित रही। परंतु तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण समानताओं और असमानताओं को पहचानने तक ही सीमित नहीं है। कई विद्वानों का यह मानना है कि तुलना का उद्देश्य केवल समानता और असमानता या तुलना और अन्तर बताना ही नहीं है बल्कि इनका उपयोग संबंधों के बड़े ढांचों में राजनैतिक परिघटना के अध्ययन के लिए करना है। ऐसा माना गया कि इससे हमारी समझ बढ़ेगी और राजनैतिक परिघटना की व्याख्या करने और सोचने समझने के दायरे में बढ़ोत्तरी होगी। (देखिए **मनोरंजन, मोहंती,** *'कम्पेरेटिव पोलिटीकल थ्योरी ऐंड थर्ड वर्ल्ड सेंसिटिविटी,' टीचिंग पोलिटिक्स, 1 ऐंड 2 1975)*

1.2.2 तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार

रोनाल्ड शिलकोट के अनुसार यह कहना कि तुलनात्मक राजनीति में सरकारों का अध्ययन किया जाता है एक अवधारणात्मक भ्रांति है। तुलनात्मक सरकार का अध्ययन सरकारों के तुलनात्मक अध्ययन तक सीमित है जबकि तुलनात्मक राजनीति के अन्तर्गत सरकारी और गैर सरकारी सभी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अन्तर्गत राजनीति से जुड़े सभी क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति का दायरा काफी विस्तृत है और इस विस्तृत अवधारणा को आधार बनाकर ही यह तय किया जा सकता है कि इसके अन्तर्गत क्या शामिल किया जाए और क्या शामिल नहीं किया जाए। इसका दायरा संकुचित करने से इसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है (**रोनाल्ड शिलकोट,** *इन्ट्रोडक्शन, थ्योरिज ऑफ कम्पेरेटिव पोलिटिक्स पृ. 4)* यहां इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि काफी लम्बे समय तक तुलनात्मक राजनीति का संबंध सरकारों और भिन्न प्रकार के शासनों के अध्ययन और पश्चिमी देशों के अध्ययन तक सीमित रहा है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अनौपवेशीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई और 'नए देशों' के अध्ययन की दिशा में भी रुचि जागृत हुई। तुलना के लिए कई इकाइयां/मामले सामने आए और इनकी तुलना की दिशा में प्रयास किया जाने लगा। राजनैतिक परिघटना और प्रक्रियाओं को समझने और समझाने के लिए नई इकाइयों का अध्ययन किया जाने लगा। राजनीति को एक पूरी व्यवस्था के रूप में समझने के लिए तुलनाएं की जाने लगीं। नए देशों के अध्ययन के साथ-साथ अध्ययन के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। इसके तहत न केवल राज्य और इसकी संस्थाओं का अध्ययन किया जाने लगा बल्कि व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों, राजनैतिक दलों, हित समूहों, सामाजिक आंदोलनों आदि का भी अध्ययन आरंभ हुआ। राजनैतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए संस्थाओं और राजनैतिक प्रक्रियाओं के कुछ खास पक्षों पर बल दिया गया जैसे राजनैतिक

बल दिया गया जैसे राजनैतिक समाजीकरण, राजनैतिक संस्कृति की पद्धतियां, हितों को प्रस्तुत करने की तकनीक और हितों को बढ़ा चढ़ा कर सामने रखना। राजनैतिक नियुक्ति की शैलियां, राजनैतिक क्षमता का विस्तार और राजनैतिक उदासीनता, शासकीय संभ्रांत वर्ग आदि। ये सुनियोजित अध्ययन अक्सर राष्ट्र निर्माण अर्थात किसी जनसंख्या की राजनैतिक, सांस्कृतिक पहचान बनाना, राज्य निर्माण अर्थात संस्थागत संरचना पैदा करना तथा आधुनिकीकरण अर्थात विकास के पश्चिमी ढर्रे पर परिवर्तन करने के सरोकारों से जुड़ा हुआ था। विश्व राजनीति में अलग-अलग वैचारिक धारणाओ नें (पश्चिमी पूंजीवाद और सोवियत समाजवाद) अधिकांश नए आजाद हुए देशों द्वारा पश्चिमी साम्राज्यवाद को खारिज करना, गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा अपनी अलग पहचान बनाना और अधिकांश देशों का समाजवादी विकास के ढर्रे के प्रति आकृष्ट होने जैसी नई परिघटनाओं के कारण विश्व स्तरीय या बड़े पैमाने पर तुलना करने के लिए अधिकांश आधुनिकीकृत मॉडलों को अप्रासंगिक बना दिया। जहां 50-60 के दशक में बड़े पैमाने के मॉडल के निर्माण के द्वारा राजनैतिक स्थिति को व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया वहीं 70 के दशक में तीसरी दुनिया की बात चल पड़ी और ये मॉडल पृष्ठभूमि में चले गए। 80 के दशक में तुलना का मापदंड बदला जिसमें क्षेत्र या छोटी इकाइयां प्रमुख हो गईं। हालांकि भूमंडलीकरण के साथ बड़े पैमाने की तुलना का महत्व फिर बढ़ा और तुलना का क्षेत्र विस्तृत हुआ जिसमें गैर राज्य और गैर सरकारी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। इसके तहत बढ़ते आर्थिक संबंधों और सूचना प्रौद्योगिक क्रांति के कारण देशों के बीच बढ़ते संबंध का भी अध्ययन किया जाने लगा। अगले भाग में तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण में हुए इन विकासों का अध्ययन करेंगे। इसमें हम इसके बदलते स्वरूप की जांच पड़ताल भी करेंगे।

1.3 तुलनात्मक राजनीति : एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

समय के साथ-साथ विषय वस्तु में परिवर्तन आया और इसके साथ-साथ तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र में भी परिवर्तन आया। तुलनात्मक राजनीति की विषय वस्तु का निर्धारण, भौगोलिक स्थल (अर्थात देश, क्षेत्र) जिसने इसके क्षेत्र का निर्धारण किया और प्रमुख विचार जिसमें सामाजिक यथार्थ और परिवर्तन शामिल था, से हुआ (पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित और देशी)। इस प्रकार इतिहास के करवट लेने के साथ-साथ अध्ययन के सरोकार भी बदले।

1.3.1 राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की शुरुआत

सबसे पहले यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन किया था। अरस्तू ने 150 राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया था और उन्हें विभिन्न शासनों में वर्गीकृत किया था। उन्होंने वर्गीकरण करते हुए इसका विवरण और आदर्श भी प्रस्तुत किया था। उन्होंने न केवल शासनों का विवरण और वर्गीकरण प्रस्तुत किया बल्कि इन राजनैतिक व्यवस्थाओं के विभिन्न प्रकारों का भी ब्यौरा दिया, जैसे प्रजातंत्र, कुलीनतंत्र, राजतंत्र आदि। उन्होंने अच्छी शासन व्यवस्था के मानदंड के आधार पर भी इनके बीच का अंतर स्पष्ट किया था। इस वर्गीकरण के आधार पर उन्होंने अच्छे और बुरे, आदर्श और विकृत शासनों के बीच का उदाहरण प्रस्तुत किया था। रोम के पॉलिबियस (201-120 ई.पू.) और सिसरो (1064-43 ई.पू.) ने भी अरस्तू के इस वर्गीकरण को स्वीकार किया था। मैकियेवेली ने 15वीं शताब्दी में (1469-1527) में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया था।

1.3.2 19वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध और 20वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के तुलनात्मक अध्ययनों में 'अच्छी व्यवस्था' या 'आदर्श राज्य' के संबंध में दार्शनिक और काल्पनिक अवधारणा हावी रही और अमूर्त

तथा आदर्शवादी शब्दावली का प्रयोग होता रहा। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में उदारवाद एक प्रमुख विचारधारा थी और विश्व राजनीति में यूरोपीय देशों का वर्चस्व था। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका पर या तो यूरोपीय उपनिवेश कायम थे या उनके पूर्व उपनिवेश होने के नाते उन पर उनका वर्चस्व था। इस युग में हुए तुलनात्मक अध्ययन में प्रमुखतः संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, शक्ति का बंटवारा और सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच संबंधों का अध्ययन किया गया जिनमें प्रमुख हैं – जेम्स ब्राइसेस का *मॉडर्न डेमोक्रेसिज* (1921), हरमन फाइनेर्स का *थ्योरी ऐंड प्रैक्टिस ऑफ माडर्न गवर्नमेंट्स* (1932) और कार्ल जे. फ्रेडरिक का *कंस्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऐंड डेमोक्रेसी* (1932), रोबर्टो माइकल का *पोलिटिकल पार्टी* (1915) और एम ड्यूवर्गर का *पोलिटिकल पार्टीज* (1950)। इनमें मुख्य रूप से ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों की संस्थाओं, सरकारों और शासन प्रकारों का अध्ययन किया गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि ये अध्ययन इस अर्थ में शुद्धतः तुलनात्मक नहीं थे क्योंकि इनके विश्लेषण में बड़ी संख्या में देशों को छोड़ दिया गया था। इन थोड़े देशों के अध्ययन से निकाला गया सामान्य निष्कर्ष शेष दुनिया के लिए सही नहीं होता। यहां यह बात बता देना आवश्यक है कि शेष दुनिया को अध्ययन से अलग रखना विश्व राजनीति में यूरोप के वर्चस्व का परिचायक है। परंतु इस दौरान विश्व पर यूरोप की पकड़ कमजोर होने लगी थी और उत्तरी अमेरिका दुनिया पर हावी होने लगा था। समकालीन इतिहासों में यूरोप को केंद्र बनाया गया और शेष दुनिया (उपनिवेश से आजाद हुए देशों को शामिल नहीं किया गया। यह कहा गया कि इनका कोई इतिहास नहीं है या इनका इतिहास पश्चिम के विकसित देशों से जुड़ा है। ऊपर जिन पुस्तकों का उल्लेख किया गया है उनमें पश्चिमी उदारवादी प्रजातंत्र की आदर्शवादी मूल्यों में आस्था प्रकट की गई है। उनमें नस्ल और सभ्यता के श्रेष्ठता की झलक मिलती है। इन ग्रंथों में उपनिवेशों/पूर्व उपनिवेशों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया गया है।

1.3.3 द्वितीय विश्वयुद्ध और उसके बाद

1930 तक आते-आते दुनिया की राजनैतिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया। 1917 में रूस में बॉलशेविक क्रांति हुई जिसने विश्व राजनीति में समाजवाद को शोषितों की विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया। यह पश्चिमी उदारवाद और पूंजीवाद की आलोचना भी थी और विकल्प भी था। द्वितीय विश्वयुद्ध के अन्त में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं मसलन यूरोपीय (ब्रिटिश) वर्चस्व कम होने लगा, विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय और विस्तार तथा दुनिया का दो विचारधारात्मक शिविरों अर्थात (पश्चिमी) पूंजीवाद और (पूर्वी) समाजवाद में विभाजित हो जाना। द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होते-होते 'शेष दुनिया' के अधिकांश देशों ने अपने को यूरोपीय साम्राज्यवाद से मुक्त करा लिया। उपनिवेशों की समाप्ति के बाद विकास, आधुनिकीकरण, राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण आदि की अवधारणाओं में परिवर्तन हुआ और 'नए राष्ट्रों' के राजनैतिक संभ्रांतों के बीच 'राष्ट्रीय नारे' लोकप्रिय हुए। सिद्धांततः ये 'नए राष्ट्र' विकास के पश्चिमी पूंजीवादी ढर्रे पर चलने के लिए बाध्य नहीं रह गए। एक ओर जहां एशिया, अमेरिका और लैटिन अमेरिका के नए शासकीय वर्ग का झुकाव समाजवाद की ओर था वहीं अच्छी खासी संख्या में नए आजाद हुए देशों ने दोनों ही महाशक्तियों से अपने को अलग रखने का प्रयत्न किया और दोनों के प्रति गुट निरपेक्ष रहे। इनमें से कितनों ने अपने विकास का रास्ता खुद तय किया। कुछ ने समाजवादी रास्ता अपनाया जैसे तंजानिया में उज्जमा और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों से सूत्र ग्रहण किए गए। यहां यह बता देना आवश्यक है कि 1940 के दशक तक सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन प्रमुखतः संस्थाओं, उन्हें नियमित करने वाले कानूनी-संवैधानिक सिद्धांतों और पश्चिमी (यूरोपीय) उदारवादी प्रजातंत्रों में उनकी कार्य पद्धति तक सीमित रहा। ऊपर्युक्त विकासों के संदर्भ में 1950 के दशक के मध्य में संस्थागत दृष्टिकोणों की कड़ी आलोचना हुई। इस आलोचना की जड़ें व्यवहारवाद में निहित थीं

जिसका उदय राजनीति विज्ञान में एक वैज्ञानिक रुझान पैदा करने और राजनीति विज्ञान का विकास करने के लिए हुआ था। इस व्यवहारवादी आंदोलन में तथ्यों की जांच पड़ताल पर बल दिया गया। इसमें मूल्य निरपेक्ष, गैर आदर्शवादी, वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण और व्याख्या प्रस्तुत की गई। सामाजिक यथार्थ का अध्ययन करने के कम में व्यवहारवादियों ने इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ढूंढ़ने का प्रयास किया कि लोगों का व्यवहार राजनैतिक क्यों होता है और इसके परिणामस्वरूप राजनैतिक व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं ऐसा क्यों होता है? लोगों के व्यवहारों के अन्तर और राजनैतिक प्रक्रियाओं तथा राजनैतिक व्यवस्थाओं के बारे में 'क्यों संबंधी प्रश्न' में तुलनात्मक अध्ययन का स्वरूप बदल दिया। अब यह संस्थाओं के कानूनी-औपचारिक अध्ययन तक ही सीमित नहीं रहा। 1955 में रॉय मैक्रिडिस ने मौजूदा तुलनात्मक अध्ययन की यह कहकर आलोचना की कि इसमें गैर औपचारिक राजनैतिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा औपचारिक संस्थाओं को महत्व दिया जाता है, इसमें विश्लेषण की जगह वर्णन होता है और इसमें किसी एक खास स्थिति का वर्णन किया जाता है तुलना नहीं की जाती (रॉय मैक्रिडिस, द स्टडी ऑफ कम्परेटिव गवर्नमेंट, न्यूयार्क रैंडम हाउस, 1955)। हैरी इकस्टिन का मानना है कि इस अवधि में तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्रा में एक परिवर्तन दिखाई देता है। यह परिवर्तन बदलती विश्व राजनीति का परिणाम है। इसके द्वारा राजनीति की अवधारणा को बदला गया और तुलना के आधार विकसित हुए। (हैरी इकस्टिन, 'ए प्रस्पेक्टिव ऑन कम्परेटिव पॉलिटिक्स, पास्ट ऐंड प्रेज़ेन्ट' हैरी इकस्टिन ऐंड डेविड एप्टर सम्पादित, कम्परेटिव पॉलिटिक्स: ए रीडर, न्यू यार्क, फ्री प्रेस, 1963)। गैब्रियल एलमोंड और अमेरिकन सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल्स कमिटी ऑन कम्परेटिव पॉलिटिक्स (1954 में स्थापित) के उनके सहयोगियों ने उस परम्परागत और केवल पश्चिमी दुनिया पर आधारित विचारधारा को खारिज किया और साथ ही साथ उस भाषा की भी आलोचना की जिसका निर्माण एक संकुचित दायरे में हुआ था। उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत और प्रविधि विकसित करने की बात की जिसके द्वारा सभी प्रकार की राजनैतिक व्यवस्थाओं-प्रारंभिक या विकसित, जनतांत्रिक या गैर जनतांत्रिक, पश्चिमी या गैर पश्चिमी- का अध्ययन किया जा सके। भौगोलिक या क्षेत्रीय दृष्टि के विस्तार के साथ-साथ राजनैतिक दृष्टि का भी विकास हुआ और औपचारिक राजनैतिक संस्थाओं के परम्परागत और संकीर्ण दायरे वाले अध्ययन को खारिज कर दिया गया। राजनीति की अवधारणा विस्तृत हुई और इसमें 'वास्तविकता' या व्यावहारिक राजनीति पर बल दिया गया। इसमें राजनैतिक दलों, हित समूहों, चुनावों के रुझानों, दृष्टिकोणों आदि जैसे कम औपचारिक और संरचनाकृत प्राधिकरणों का अध्ययन किया गया *(गैब्रियल एलमोंड़,* **पोलिटिकल डेवलप्मेंट, बोस्टन, 1970**)। औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से दूर हटते ही राज्य की अवधारणा पर बल दिया जाना भी कम हुआ। हम पहले बता चुके हैं कि विश्व पटल पर बड़ी संख्या में राष्ट्रों के उदित होने के परिणामस्वरूप एक ऐसे ढांचे के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई जिसके तहत व्यापक रूप से तुलना की जा सके। इससे राजनैतिक व्यवस्था जैसी सम्मिलित अमूर्त अवधारणाओं का जन्म हुआ। 'व्यवस्था' की इस अवधारणा ने राज्य की अवधारणा का स्थान ले लिया। इससे विद्वानों को औपचारिक कानून से अलग उन सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं पर विचार करने में मदद मिली जो गैर पश्चिमी राजनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा राजनीति के अध्ययन क्षेत्रा में 'पूर्व राज्य'/'गैर राज्य' समाजों और ऐसे कार्यों तथा पद जिनका राज्य के साथ सीधा संबंध नहीं माना जाता था, को भी शामिल किया गया। संस्थाओं के वास्तविक कार्यों और प्रथाओं पर बल देने के साथ-साथ अनुसंधान की समस्याओं को इन संस्थाओं की कानूनी शक्तियों के संदर्भ में न परिभाषित करके उनके कार्यों और परस्पर संबंध और लोकनीति के निर्माण तथा कार्यान्वयन में उनकी भूमिका के आधार पर परिभाषित किया जाने लगा। इसके परिणामस्वरूप संरचनात्मक-कार्य पद्धति का उदय हुआ जिसमें कुछ कार्यों को सभी समाजों के लिए आवश्यक माना गया और विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक संरचनाओं के बीच इन कार्यों के कार्यान्वयन और निष्पादन की तुलना की गई **(पीटर मेयर,** *'कम्परेटिव पॉलिटिक्स: ऐन ओवरव्यू', पृ. 315)।*

एक ओर जहां व्यवस्थाओं और संरचनात्मक कार्य प्रणाली के सार्वभौम ढांचे ने पश्चिमी विद्वानों को एक बड़े क्षेत्र में राजनैतिक व्यवस्थाओं पर संरचनाओं और व्यवहारों के अध्ययन में मदद की वहीं दूसरी ओर 'नए राष्ट्रों' के उदय ने पश्चिमी तुलनावादियों को आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन के अध्ययन का अवसर प्रदान किया। वियारडा के अनुसार मुख्य रूप से 60 के दशक में ही समकालीन विद्वानों ने तुलनात्मक राजनैतिक अध्ययन की शुरुआत की। विडम्बना यह है कि इनमें से अधिकांश विद्वानों के लिए ये 'नए राष्ट्र' सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए 'जीवित प्रयोगशालाएं' बनीं। वियारडा उन 'महत्वपूर्ण समयों' की विस्तार से चर्चा करते हैं जिस समय राजनैतिक परिवर्तन के अध्ययन को अनूठा अवसर मिला और नई प्रविधियों का विकास और उनके अध्ययन के नए दृष्टिकोण से परिचित हुए। इसी अवधि के दौरान तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में नूतन और रोचक, सैद्धांतिक और अवधारणात्मक विचार सामने आए जैसे राजनैतिक संस्कृति का अध्ययन, राजनैतिक समाजीकरण, विकासवाद, निर्भरता और परस्पर निर्भरता, कॉरपोरेट व्यवस्था, नौकरशाही-निरंकुशतावाद और प्रजातंत्र में बाद का संक्रमण आदि। *(हॉवर्ड जे. वियारडा, 'इज कम्परेटिव पॉलिटिक्स डेड? रिथिंकिंग द फिल्ड इन द पोस्ट-कोल्ड वार इरा', थर्ड वर्ल्ड क्वाटरली, वौल्यूम 19, नं. 5)*

इस अवधि में ईस्टन की राजनैतिक व्यवस्था डेश की सामाजिक लामबन्दी और शील की केंद्र और परिधि जैसे सार्वभौमिक मॉडल सामने आए। ऐप्टर, रोक्कन, आइन्सटैट और वार्ड द्वारा प्रतिपादित आधुनिकीकरण के सिद्धांत और ऐलमॉन्ड, कोल मैन, पाई और वर्बा के राजनैतिक विकास के सिद्धांत को दुनिया भर में मान्यता मिली। यह दावा किया गया कि यह सिद्धांत सभी सांस्कृतिक और वैचारिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं और सभी जगह की राजनैतिक प्रक्रिया की व्याख्या में सक्षम हैं। इस चरण में तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण में हुए विकास के साथ-साथ संयुक्त राज्य का सैनिक संधियों और विदेशी अनुदान के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप भी सामने आया। इस अवधि में हुए अधिकांश अनुसंधानों को न केवल शोध संस्थाओं से धन प्राप्त हुआ बल्कि इसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के लिए भी किया गया। लैटिन अमेरिका में कैमेलॉट परियोजना और भारत में हिमालय परियोजना इसका सर्वाधिक प्रतीकात्मक उदाहरण है। इस अवधि में कई महत्वपूर्ण कार्य सामने आए जैसे ऐप्टर का घाना पर किया गया अध्ययन। 1960 में प्रकाशित एलमन्ड और कौलमैन का ग्रंथ पॉलिटिक्स ऑफ डेवेल्पिंग एरियाज में नए ' तुलनात्मक राजनैतिक आंदोलन' की विशेषताओं को परिभाषित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से 1969 में प्रकाशित शीर्षक पत्रिका में इसी प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। 'विकासवाद' सम्भवत: इस समय की सबसे प्रमुख अवधारणा थी। काफी हद तक 'विकासशील' देशों में पनप रहे मार्क्सवाद-लेनीनवाद को रोकने और वहां गैर साम्यवादी विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई अमेरिकी विदेश नीति के हित में विकासवाद का उपयोग किया गया। *(हॉवर्ड जे वियारडा, 'इज कम्परेटिव पॉलिटिक्स डेड? रिथिंकिंग द फिल्ड इन द पोस्ट-कोल्ड वार इरा,' थर्ड वर्ल्ड क्वाटरली, वौल्यूम 19 नं.5, पृ.937)*

1.3.4 1970 का दशक और विकासवाद की चुनौतियां

1970 के दशक में विकासवाद के अमूर्त मॉडलों की पक्षधरता के लिए आलोचना की गई जिसके तहत एक सार्वभौमिक ढांचे के अन्तर्गत विशेष राजनैतिक/सामाजिक/सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के अन्तर को समाप्त कर दिया गया। इन मॉडलों की जातीयता पर बल दिए जाने की आलोचना की गई और अल्प विकास के सिद्धांत विकसित करने के लिए तीसरी दुनिया पर बल देने की बात कही गई। इन आलोचनाओं में विकासशील देशों के पिछड़ेपन के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया गया। 1970 के दशक के आरंभ में विकासवाद के समक्ष दो चुनौतियां थी जिसकी तरफ सब लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ – क) निर्भरता, ख) कॉरपोरेट सिद्धांत। निर्भरता सिद्धांत ने क) घरेलू वर्ग के कारकों और ख) विकास में अन्तरराष्ट्रीय बाजार और शक्ति कारकों को नजरअंदाज करने के लिए

विकासवाद के मॉडल की आलोचना की। इसमें खासतौर पर अमेरिका की विदेश नीति और बहुराष्ट्रीय निगमों की आलोचना थी जिसमें विकासवाद की धारणा के विपरीत यह स्थापित किया गया था कि औद्योगीकृत राष्ट्रों का विकास और विकासशील देशों का विकास एक साथ नहीं चल सकता है। निर्भरता सिद्धांत का यह मानना है कि पश्चिम का विकास गैर पश्चिम के कंधों और कीमत पर हुआ है। **आन्द्रे गुंडरे फ्रैंक** की पुस्तक *कैपीटलिज्म ऐंड अंडरडेवलेप्मेंट इन लैटिन अमेरिका* (1967) **वाल्टर रोडनी** की पुस्तक *हाउ यूरोप अंडरडेवेलप्ड अफ्रीका* (1972) और **मैलकम कैडवेल्स** की *द वेल्थ ऑफ सम नेशन्स (1979)* में यह विचार व्यक्त किया गया कि पूंजीवाद के प्रसार से दुनिया के कई देशों में विकास नहीं बल्कि अल्पविकास हुआ है। मार्क्सवादी आलोचकों ने निर्भरता सिद्धांत की आलोचना करते हुए यह कहा कि शोषण का आधार अधिशेष पर कब्जा जमाने से होता है और इसे राष्ट्रीय सीमा में नहीं बांधा जाना चाहिए। विश्व स्तर पर फैली पूंजीवादी व्यवस्था में मेट्रोपोलिटन बुर्जुआ वर्ग केंद्र में होता है और देशी बुर्जुआ वर्ग परिधि में होता है और इनके बीच एक जटिल गठबंधन होता है जिनकी मदद से ये शोषण करते हैं। कॉरपोरेट सिद्धांत ने यूरोपीय अमेरिकी जातीय केंद्रीयता के लिए विकासवाद की आलोचना की और यह बताया कि राज्य और राज्य-समाज संबंधों को संगठित करने के लिए वैकल्पिक, सुव्यवस्थित, नैगमिक और प्राय: निरंकुशतावादी तरीके भी मौजूद थे।

1.3.5 1980 का दशक: राज्य की वापसी

1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक में विकासवाद के खिलाफ मुहिम चलती रही और तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में कई सिद्धांत और विषय सामने आए। नौकरशाही-निरंकुशतावाद, परिवर्तन की स्थानीय अवधारणाएं, प्रजातंत्र में संक्रमण, संरचनात्मक समायोजन, नवउदारवाद और निजीकरण की राजनीति इनमें प्रमुख हैं। कुछ लोगों ने इन गतिविधियों को विकासवाद के वर्चस्व को तोड़नेवाली कार्यवाई के रूप में देखा तो कुछ लोगों ने कहा कि इससे इस क्षेत्र में विविधता आई, नए विकल्प सामने आए और इसका क्षेत्र व्यापक हुआ। **ऐलमंड** ने 1950 के दशक में ही यह धारणा सामने रखी थी कि राज्य का स्थान राजनैतिक व्यवस्था को ले लेना चाहिए जिसकी वैज्ञानिक जांच पड़ताल कर उसे उसके अनुसार परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। इस्टन ने राजनैतिक व्यवस्था की हदों और अवधारणाओं का निर्माण किया और 1980 के दशक तक राजनैतिक अध्ययन के लिए राजनैतिक व्यवस्था के महत्व की चर्चा करते रहे। **गुलीरेमो ओ डॉनेल** ने अपनी पुस्तक *इकॉनॉमिक मॉडरनाइजेशन ऐंड ब्यूरोक्रेटिक आउथोरिटेरिएनिज्म* (1973) में लैटिन अमेरिका और खासकर अर्जेन्टिना में नौकरशाहीपरस्त निरंकुशतावाद का अध्ययन किया और इस प्रकार 60 और 70 के दशक में राज्य की ओर विद्वानों का ध्यान गया। **रैल्फ मिलिबैंड** ने *द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी* (1969) में भी इसी विषय पर विचार किया। **निकोस पोलैन्जा** ने *स्टेट, पावर, सोशिएलिज्म* (1978) और राजनैतिक समाजशास्त्री **पीटर इवेन्स**, **ठेडा स्कॉकपॉल**, और **अन्य** ने *ब्रिंगिंग स्टेट इन* में राज्य को केंद्र में रख कर विचार किया।

1.3.6 20वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध: भूमंडलीकरण और उभरती प्रवृत्तियां

क) **व्यवस्थाओं का अध्ययन:** 1960 से लेकर 1980 के दशक में तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण में काफी विकास हुआ। इसका क्षेत्र विस्तृत हुआ और इसमें बड़ी संख्या में देश शामिल किए गए। नीति, विचारधारा, शासकीय अनुभव और इसी प्रकार के कई मानदंडों का उपयोग किया गया। हालांकि 1980 के दशक में सामान्य सिद्धांत से अलग हटकर संदर्भ की प्रासंगिकता पर बल दिया जाने लगा। अंशत: यह सामाजिक विज्ञानों में ऐतिहासिक जांच पड़ताल के फिर से बढ़ रहे प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है। यह उस 'ऐतिहासिक समाजशास्त्र' के उदय को भी दर्शाता है जो परिघटनाओं को व्यापक और बृहद संदर्भ में देखने की कोशिश करता है। (**थेडा स्कॉकपॉल ऐंड एम. सोमर्स**, *'द यूज ऑफ कम्परेटिव हिस्ट्री इन मैक्रो-सोशल इन्क्वायरी'*, *कम्परेटिव स्टडीज इन*

सोसाइटी ऐंड हिस्ट्री, नं. 22, 1980 ऐंड **पी. एब्रम्स**, *हिस्टॉरिकल सोशिओलॉजी, इथेका,* 1982)। अब मॉडल की बात न करके किसी खास उद्देश्य या मामले को गहराई से समझने पर ज्यादा बल दिया जाने लगा है जहां आधुनिक गुणात्मक और संदर्भयुक्त आंकड़े का मूल्यांकन किया जा सके और जहां विशेष संस्थागत परिस्थितियों या खास राजनैतिक संस्कृतियों की जानकारी प्राप्त की जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृति आधारित अध्ययनों का जोर बढ़ा (अंग्रेजी बोलने वाले देश, इस्लाम धर्म को मानने वाले देश) और राष्ट्रीयता आधारित देश (जैसे इंगलैंड, भारत) और यहां तक कि संस्थागत विशिष्ट राष्ट्र (उदाहरणस्वरूप किसी खास शासन के अन्तर्गत भारत) पर विशेष बल दिया जाने लगा। 'बड़ी व्यवस्थाओं' पर बल दिया जाने लगा और मॉडल निर्माण का ह्रास हुआ। विशिष्ट संदर्भ और संस्कृतियों पर बल दिए जाने के कारण तुलना का मानदंड व्यापक किया गया। 'छोटी व्यवस्थाओं' या क्षेत्रों के स्तरों पर तुलना की प्रवृत्ति जारी रही जैसे इस्लाम धर्म को मानने वाले लैटिन अमेरिका के देश, उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया आदि।

ख) **नागरिक समाज और जनतांत्रिक दृष्टिकोण**: सोवियत संघ के विघटन के बाद 'इतिहास का अंत' की अवधारणा सामने आई। **फ्रैंसिस फुक्युयामा** ने *द एन्ड ऑफ हिस्ट्री* (1989) नामक लेख लिखा। बाद में उन्होंने इसी विषय पर *द एन्ड ऑफ हिस्ट्री ऐन्ड द लास्ट मैन* (1992) नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने अपने इस लेख और पुस्तक में कहा कि 'मानव सरकार के अन्तिम स्वरूप' में उदारवादी प्रजातंत्र की स्थापना और विजय से विचारों का इतिहास समाप्त हो गया। 'इतिहास का अन्त' की बात करके वस्तुत: पश्चिमी उदारवादी प्रजातंत्र के वर्चस्व पर ही बल दिया गया। यह 1950 के दशक से चली आ रही 'विचारधारा का अंत' विषय पर हो रही बहस का भी परिचायक है जिसका जन्म शीतयुद्ध की चरम अवस्था में और पश्चिम में साम्यवाद के पतन के संदर्भ में हुआ था। पश्चिमी उदारवादी विद्वानों ने यह बात सामने रखी कि पश्चिम के औद्योगिक समाजों में हुए आर्थिक विकास से राजनैतिक समस्याएं हल हो गईं जैसे आजादी और राज्य शक्ति के मामले, मजदूरों के अधिकार आदि जो औद्योगीकरण के साथ-साथ आगे बढ़े। अमेरिका के समाजशास्त्री **डेनियल बेल** ने अपनी पुस्तक (*द ऐन्ड ऑफ आइडियोलॉजी?: ऑन द इग्जॉशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इन द 1950ज़, 1960ज़*) में बताया कि इस विकास के संदर्भ में एक विचारात्मक सर्व सम्मति थी या राजनैतिक व्यवहार के मुद्दे पर वैचारिक मतभेदों को स्थगित कर दिया गया था। 1980 के दशक में 'इतिहास के अंत' के विचार के साथ-साथ भूमंडलीकरण की नई परिघटना सामने आई। भूमंडलीकरण ऐसी परिस्थितियों, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों का नाम है जो पूरे विश्व को इस प्रकार एक सूत्र में बांधता है कि विश्व के एक कोने में हो रही घटना का असर विश्व के दूसरे कोने में पड़ता है। यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि इस भूमंडलीकृत दुनिया में अभी भी सारी घटनाएं पश्चिमी पूंजीवाद के इर्द गिर्द नाच रही हैं। पूंजीवाद की तथाकथित विजय के संदर्भ में नागरिक समाज और जनतांत्रीकरण के अध्ययन संबंधी दृष्टिकोणों में नागरिक समाज का महत्व बढ़ा और आधुनिक पूंजीवादी विश्व में व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की बात की जाने लगी।

इसके अलावा दृष्टिकोण में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आया जिसमें नागरिक समाज और जनतांत्रीकरण के प्रश्न को केंद्र में रखा गया। इस प्रकार एक तरफ जहां बाजार जनतंत्र के विकास के लिए पश्चिमी पूंजीवाद के समकालीन हित से संबंधित अध्ययन हुए तो दूसरी ओर स्वायत्ता प्राप्त करने वाले, जनजातियों के आंदोलन, दलित आंदोलन, निम्न जातियों के आंदोलन, महिलाओं के आंदोलन, पर्यावरण के आंदोलन जैसे जन आंदोलनों को केंद्र में रखकर अध्ययन किए गए। ये आंदोलन पूंजी के हित और जन अधिकारों के बीच होने वाली टक्कर के परिणाम थे। ये अर्थव्यवस्था भूमंडलीय पूंजी के युग में आनेवाले उदारवाद और बदलाव का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण में अस्मिता, पर्यावरण, जातीयता, लिंग, नस्ल आदि सरोकारों के नए आयाम जुड़े। (देखिए **मनोरंजन मोहन्ती**, *कन्टेम्प्ररी इन्डियन पॉलिटिकल थ्योरी,* 2000)।

ग) **सूचना, संग्रहण और प्रसार:** सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब जैसे अभूतपूर्व विकास भूमंडलीकरण के महत्वपूर्ण पक्ष और निर्धारक तत्व हैं। इसके कारण उत्पादन, संग्रहण और आंकड़े का विश्लेषण आसान हो गया है और इसे पूरी दुनिया में तेजी से फैलाया जा सकता है। इससे न केवल आंकड़ों की उपलब्धता सहज हो गई बल्कि कुछ ऐसे नए मुद्दे और विषय भी सामने आए जो राष्ट्र-राज्य की परिधि का अतिक्रमण करते हैं। इन नए विषयों के कारण समकालीन भूमंडलीकृत दुनिया के राजनैतिक परिवेश में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। सामाजिक आंदोलन के संगठनों और कार्यकर्ताओं का पूरी दुनिया में फैला सम्पर्क इसका प्रमाण है। इस प्रकार के सम्पर्क सूत्र के कारण जनतांत्रिक विचार भी तेजी से फैले। शियापास के दक्षिणी मैक्सिकन राज्य के जापासटिस्टा आंदोलन में इंटरनेट का प्रयोग किया गया था और अपने अधिकारों, सामाजिक न्याय और प्रजातंत्र के लिए किए जाने वाले संघर्ष से सबको परिचित कराने के लिए भूमंडलीय जनसंचार का उपयोग किया गया था। समकालीन विषयों में मानवाधिकारों के संवर्धन और सुरक्षा जैसे मुद्दे सामने आए जो सूचना के संग्रहण और प्रसार पर आधारित थे।

बोध प्रश्न 1

नोट : i) नीचे दिए गए स्थान में अपना उत्तर लिखिए।

ii) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए।

1) क्या यह कहना सही है कि तुलनात्मक राजनीति केवल सरकारों के अध्ययन की एक प्रविधि है ?

....

....

....

....

2) ऐतिहासिक कालक्रम में बदलते सामाजिक, राजनैतिक सरोकारों के साथ-साथ तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, क्षेत्र और विस्तार में भी अन्तर आया। इस संबंध में अपना मत प्रकट कीजिए।

....

....

....

1.4 राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता

राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता का संबंध राजनैतिक यथार्थ को समझने में इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता से है। इसके द्वारा यह जानने की कोशिश की जाती है कि किस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन इस यथार्थ को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करता है।

सबसे पहले हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सभी मनुष्यों की एक राजनैतिक रुझान होती है और यह अलग-अलग तरीकों से पूरी दुनिया में अलग-अलग सामाजिक और संस्थागत ढांचों में अभिव्यक्त होती है। यह कहा जा सकता है कि इन्हें समझना और साथ ही साथ विभिन्न राजनैतिक रुझानों और पद्धतियों को जानना राजनीति को समझने के लिए जरूरी है। तुलना करने से हम एक ठोस और व्यापक समझ कायम कर पाएंगे।

1.4.1 सैद्धांतिक निरूपण के लिए तुलना

तुलना जहां हमारी तर्क शक्ति और सोचने समझने के ढंग का एक अन्तरंग हिस्सा है वहीं अधिकांश तुलनावादियों का मानना है कि राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन में विभिन्न पद्धतियों में तुलना कर एक ऐसे सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है जो काफी हद तक कई पद्धतियों पर लागू होता है। इस प्रकार के सामान्यीकरण के लिए केवल विभिन्न देशों की सूचना इकट्ठी कर लेना ही काफी नहीं होता। विभिन्न देशों को केंद्र में रखकर तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण किया जाता है और इसके आधार पर एक सिद्धांत बनाया जाता है और उसका परीक्षण किया जाता है। इसलिए इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि तुलनात्मक अनुसंधान किस प्रकार किए जाए और उनके नियम और मानदंड क्या हों। तुलनात्मक अध्ययन में जो सामान्यीकरण किया जाता है उसमें एक से अधिक परिघटना या विभिन्न परिघटनाओं के आपसी संबंधों का निरीक्षण किया जाता है। यह निरीक्षण जितना ही व्यापक होगा उतना ही सामान्यीकरण सही होगा और इसके आधार पर बने सिद्धांत ठोस होंगे।

1.4.2 वैज्ञानिक अध्ययन के लिए तुलना

हम अगली इकाई में यह बताएंगे कि तुलनात्मक विधि से इन सिद्धांतों को वैज्ञानिक आधार और रुझान प्राप्त होता है। समाज वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक पद्धति, वैधता और विश्वसनीयता पर बल देते हैं, वे सामाजिक विज्ञान में तुलना को अनिवार्य मानते हैं क्योंकि इससे सामाजिक परिघटना के अध्ययन में 'नियंत्रण' का अनूठा अवसर मिलता है। (**जियोवन्नी सारटोरी**, *'कम्पेयर, ह्वाई ऐंड हाउ' इन मैटेइ डेगन ऐंड अलि काजानसिगिल कम्पेयरिंग नेशन्स, कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रेटिजीस, स्बसटेंस, बैकवेल, ऑक्सफोर्ड,* 1994)

1.4.3 संबंधों की व्याख्या के लिए तुलना

लम्बे समय से तुलनात्मक राजनीति के अन्तर्गत केवल राजनैतिक परिघटनाओं की समानता और असमानता, वर्गीकरण, द्विभाजन या ध्रुवीकरण किया जाना प्रतीत होता रहा है। हालांकि तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण समानताएं और असमानताएं बताने तक ही सीमित नहीं है। कई विद्वानों का यह मानना है कि तुलना करने का अर्थ केवल समानता या असमानता, तुलना या वैषम्य बताना ही नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य संबंधों के बड़े ढांचों में राजनैतिक परिघटना का अध्ययन करना है। ऐसा महसूस किया गया कि राजनैतिक परिघटना को गहरे और व्यापक रूप में समझने में मदद मिलेगी (देखिए **मनोरंजन मोहंती**, *'कम्परेटिव पोलिटिकल थ्योरी ऐंड थर्ड वर्ल्ड सेंस्टिविटी', टीचिंग पोलिटिक्स*, न. 1 और 2, 1975)।

बोध प्रश्न 2

नोट : i) नीचे दिए गए स्थान में अपना उत्तर लिखिए।

ii) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए।

1) आपके अनुसार राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की क्या उपयोगिता है ?

....

....

....

....

....

1.5 सारांश

राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति और क्षेत्र का संबंध इसकी विषय-वस्तु, इसके अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन के प्रारंभिक बिन्दु और अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित है। परंतु यह कोई स्थिर अवधारणा नहीं है बल्कि इसमें लगातार परिवर्तन होता रहा है। एक ओर जहां आरंभिक अध्ययनों में सरकारों और शासकों का पर्यवेक्षण होता रहा वहीं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुई तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पश्चिमी देशों में संस्थाओं के औपचारिक कानूनी ढांचों का अध्ययन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के अन्त में विश्व पटल पर कई 'नए राष्ट्रों' का उदय हुआ जिन्होंने औपनिवेशिक शासन से अपने को मुक्त किया। उदारवाद के वर्चस्व को साम्यवाद ने चुनौती दी और विश्व पटल पर सोवियत संघ ने अपनी शक्तिशाली उपस्थिति दर्ज की। अभी तक तुलनावादियों के सामने एक मात्र ढांचा उपस्थित था जिसे विद्वानों ने चुनौती दी और राजनैतिक रुझानों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए नई पद्धतियां सामने आईं। 'व्यवस्थाओं' और 'संरचना-कार्य' की अवधारणा सामने आई। पश्चिमी विद्वानों, खास कर अमेरिकी विद्वानों, द्वारा विकासवाद, आधुनिकीकरण जैसी परिघटना का अध्ययन करने के लिए इन ढांचों का अध्ययन किया गया। नए स्वतंत्र राष्ट्रों के राजनैतिक संभ्रांतों ने जहां विकास, राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण जैसी अवधारणाओं को अपने अध्ययन का विषय बनाया वहीं कई मामलों में उन्होंने अपना वैचारिक दृष्टिकोण विकसित किया और दोनों ही विचारात्मक धड़ों से अपने आप को मुक्त रखा। 1980 के दशक के अन्त में 'व्यवस्था' के ढांचे के अन्तर्गत राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन पर दिए जाने वाले बल में ह्रास आया और क्षेत्रीय व्यवस्थापरक अध्ययनों का महत्व बढ़ा। इन अध्ययनों में राज्य पर बल दिए जाने के कारण नागरिक समाज के भीतर शक्ति संरचना और इसके राजनीतिक रूपों के अध्ययन की प्रवृत्ति बढ़ी।

तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्थाओं और संरचना-कार्यों पर आधारित अध्ययन में इसे नजरअंदाज कर दिया गया था। सोवियत संघ के पतन के बाद पश्चिमी इतिहासकारों ने 'इतिहास के अंत' की घोषणा करते हुए उदारवाद और पूंजीवाद के विजय की उद्घोषणा की। 1980 के दशक में पूंजी, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और सूचना का भूमंडलीकरण हुआ। इससे तुलनावादी विद्वान भी प्रभावित हुए और उन्होंने 'प्रजातंत्र की ओर संक्रमण', 'भूमंडलीय बाजार', 'नागरिक समाज' जैसे सार्वभौमिक और एकरूप अभिव्यक्तियों का उपयोग किया। इस प्रकार की अभिव्यक्तियों से ऐसा लगता है कि अब कोई मतभेद, अनिश्चितता, प्रतिद्वंद्विता नहीं रह गई जिसकी तुलना करने की जरूरत है। हालांकि इस परिघटना पर अलग दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। हालांकि कुछ विद्वानों ने नागरिक समाज के विकास को भूमंडलीय पूंजीवाद को चुनौती के रूप में देखा है जिसका जन्म पूरे विश्व में हुए जन आंदोलनों और मजदूरों के आंदोलनों से हुआ है।

बोध प्रश्न 3

नोट : i) नीचे दिए गए स्थान में अपना उत्तर लिखिए।

ii) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए।

1) तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र को निर्धारित करने वाली विशिष्टताएं क्या हैं ?

....

....

....

....

2) 20वीं शताब्दी में तुलनात्मक अध्ययन का विकास निरूपित करें। इसमें निम्नलिखित पक्षों पर विचार करें:

   क) द्वितीय विश्वयुद्ध के पहले और बाद की अवधि की विशेषताएं, ख) विकासवाद और इसकी आलोचना, ग) 20वीं शताब्दी के अंत में हुई गतिविधियां।

   ....

   ....

   ....

   ....

3) राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन संबंधों के ढांचे में राजनैतिक परिघटना की व्याख्या की जाती है। इस वक्तव्य के आलोक में औपनिवेशिक साम्राज्यों के अंत होने से लेकर शीतयुद्ध तक और भूमंडलीकरण युग तक तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों पर विचार कीजिए।

   ....

   ....

   ....

   ....

1.6 शब्दावली

व्यवहारवाद : इस मत के अनुसार सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण केवल व्यवहारों के निरीक्षण पर आधारित होना चाहिए। इसी के आधार पर अनुसंधान के लिए आंकड़े प्राप्त करने चाहिए। नागरिक समाज के कई अर्थ हैं। कुल मिलाकर इसे स्वायत्त समूहों और संगठनों का क्षेत्र माना जाता है। यह एक निजी क्षेत्र है जो सार्वजनिक सत्ता से स्वतंत्र है।

समनरूप स्थिति : किसी भी राजनैतिक परिघटना के लिए अनुकूल परिस्थितियां या पक्ष। यह किसी भी प्रकार की क्रांति या जनतांत्रिक भागीदारी के लिए अनिवार्य और आवश्यक शर्त है।

नियंत्रण : इस नियंत्रण का तात्पर्य एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रयोग से है जहां एक समानान्तर प्रयोग या एक समूह की स्थापना (नियंत्रण स्थापना) की जाती है। इसका उद्देश्य दूसरे प्रयोगों के लिए तुलना का मानदंड स्थापित करना होता है। अध्ययन में दृश्य माध्यम के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किए गए प्रयोग में नियंत्रण समूह को उस परिस्थिति (दृश्य माध्यम) को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा जिसके प्रभाव का अध्ययन किया जाना है।

जनतंत्रीकरण : जनतंत्र के उत्थान की प्रक्रिया, खासतौर पर आधारभूत स्वतंत्रता प्रदान करना, जनता की भागीदारी में बढ़ोत्तरी और चुनाव में हिस्सेदारी।

विवरणात्मक : विस्तार से तथ्यों का उद्घाटन, विशेषताओं और योगदानों का वर्णन।

द्विभाजन : दो मजबूत विपरीत समूहों या वर्गों में विभाजन।

यूरोपीय केंद्रित : यूरोपीय मूल्यों, विश्वासों और सिद्धांतों को अन्य संस्कृतियों और समूहों पर लागू करना और पूर्वाग्रह रखना।

भूमंडलीकरण : भूमंडलीकरण ऐसा वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवेश है जिसने दुनिया को इस प्रकार एक सूत्र में बांध दिया है कि दुनिया के एक कोने में हुई घटना का असर तुरंत दुनिया के दूसरे कोने में पड़ता है।

विधि : आंकड़ों के अनुप्रयोग के लिए सिद्धांतों के संघटन को विधि कहते हैं। इसे 'अवधारणात्मक योजना' भी कहते हैं। तुलनात्मक (एक से अधिक मामलों का उपयोग), एकल (एक उदाहरण का अध्ययन) और ऐतिहासिक; (समय और शृंखला का उपयोग) कुछ विधियां है। विधि 'सोच के बारे में सोच' अधिक है।

प्रणाली विज्ञान : अनुसंधान की विभिन्न प्रणालियों का अध्ययन, अनुसंधान के लिए बनाए जाने वाले प्रश्न, घटनाओं और राजनैतिक प्रतिफलनों को व्याख्यायित करने के लिए सिद्धांतों का निर्माण, और अनुसंधान डिजाइन का विकास

मॉडल : साधारण शब्दों में एक बौद्धिक प्रयास है जो पुनरावृत्ति, अपरिवर्तन, खासियत पर बल देने के लिए यथार्थ को सरल रूप में प्रस्तुत करता है, जो इसे प्रदेशों या योगदानों के समूह के रूप में पेश करता है। दूसरे शब्दों में मॉडल और प्रकार एक दूसरे के पर्याय हैं

नव उदारतावाद : क्लासिकल राजनैतिक अर्थव्यवस्था का अद्यतन रूप, जिसमें बाजार, व्यक्तिवादिता को बढ़ावा देने और राज्य नियंत्रण को कम करने पर बल दिया गया है।

आदर्श : मूल्य और आचार संहिता : इसमें 'क्या है' से ज्यादा 'क्या होना चाहिए' पर विचार किया जाता है

उत्तर व्यवहारवाद : 1970 के बाद का समय और ऐसी प्रविधि जिसके अनुसार राजनैतिक दुनिया का पर्यविक्षण और विश्लेषण कुछ सैद्धांतिक और मूल्य पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है। अत: विश्लेषण के द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में परेशानी है।

निजीकरण : राज्य संपदा का सार्वजनिक से निजी क्षेत्रा को स्थानांतरण, राज्य उत्तरदायित्व में कमी।

व्यवस्था सिद्धांत : इस सिद्धांत के अनुसार राजनैतिक व्यवस्था आत्म नियंत्रित व्यवस्था है जो मांग और समर्थन के अनुसार निर्णय लेता है।

सिद्धांत : दुनिया कैसे 'काम' करती है। इस संबंध में निश्चित और तर्क सम्मत वक्तव्य। इसे सामूहिक तौर पर अनुभववादी सिद्धांत (आदर्श के विपरीत) जाना जाता है, ये वक्तव्य विभिन्न परिवर्तनशील कारकों के बीच के संबंध का दावा करते हैं जिनका व्यवस्था परक तुलनात्मक विश्लेषण द्वारा परिक्षण किया जा सकता है।

1.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें और लेख

लैंडमैन, टॉड, *इश्यूज ऐंड मेथड्स इन कम्परेटिव पॉलिटिक्स: ऐन इन्ट्रोडक्शन*, रूटलेज, लंदन, 2000

मेयर, पीटर, 'कम्परेटिव पॉलिटिक्स: ऐन ओवरव्यू', आर.ई.गुडीन ऐंड एच. क्लिंगमैन संपा. *द न्यू हैंडबुक ऑफ पोलिटिकल साइंस*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 1996

मोहंती, मनोरंजन, मूविंग द सेंटर इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थॉट ऐंड पॉलिटिकल थ्योरी, *कंटम्परेरी इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी*, संस्कृति, नई दिल्ली, 2000

सटोरी, गियोवानी, 'कम्पेयर व्हाई ऐंड हाउ,' मैतेयी डोगन और अलि कजानसिगिल की संपादित पुस्तक *कम्पेयरिंग नेशन्स, कंसेप्ट्स, स्ट्रेटजी, सबस्टांस*, ब्लैकवेल, ऑक्सफोर्ड, 1994

वियारडा, हावर्ड जे., *इज कम्परेटिव पॉलिटिक्स डेड? रीथिंकिंग द फिल्ड इन द पोस्ट कोल्ड वार येरा*, थर्ड वर्ल्ड क्वाटरली, भाग 19 अंक 5

1.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) नहीं, यह सरकारों के अध्ययन करने की विधि मात्र नहीं है। इसमें सरकार के कामकाज से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है तथा अमूर्त सार्वभौम प्रारूपों का निर्माण होता है जिसके द्वारा सभी इकाइयों में होने वाली प्रक्रियाओं और राजनैतिक परिघटना को व्याख्यायित किया जा सके। विस्तार के लिए देखिए भाग 1.2.2
2) भौगोलिक विस्तार के साथ-साथ विचारों और सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक राजनीति की विषय-वस्तु का विकास और विस्तार हो रहा है। अंत: यह कई महत्वपूर्ण चरणों से गुजर चुकी है और इसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भाग 1.3

बोध प्रश्न 2

1) सिद्धांत बनाने, मुद्दों और समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण करने, परिघटना की व्याख्या करने आदि के लिए तुलनात्मक राजनीति उपयोगी है।

बोध प्रश्न 3

1) देखिए भाग 1.5
2) देखिए उपभाग 1.3.6
3) भाग 1.3 के आधार पर अपना उत्तर लिखिए।